जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 67 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 9 जनवरी, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

गहलोत ने सभी घोड़े खोल दिये हैं, ए.आई.सी.सी. में भारी पद पाने के लिये!

इसी संदर्भ में अपने विश्वासी दायें हाथ को दिल्ली में नियुक्ति दिलाई है, जिससे शशिकांत उन्हें पूरा ''फीडबैक'' देते रहें कि दिल्ली में कांग्रेस में क्या हो रहा है

- फिर शशिकांत के फीडबैक के आधार पर, गहलोत अपने राजनीतिक कदम उठायें व चाल चलें।
- साथ ही, गहलोत हरदम की तरह दिल्ली में दोनों हाथों से पैसा बिखेर रहे हैं, पुराने महारथियों को उनके लिये, दिल्ली में लॉबीइंग करने के लिये, माहौल बनाने के लिये।
- इस बार, एक फर्क जरूर है, राहुल गांधी के सबसे नज़दीक माने जाने वाले के.सी. वेणुगोपाल, जिनका संगठन महामंत्री के रूप से पाँच साल का कार्यकाल अब पूरा हो रहा है और वो रिटायर होने के कगार पर हैं, भी गहलोत के पक्ष में खड़े होते से नज़र आ रहे हैं, वेणुगोपाल, गहलोत की, पार्टी का फायनैंसर होने की क्षमता पहचानते हैं। वेणुगोपाल पार्टी अध्यक्ष का राजनैतिक सलाहकार बनना चाहते हैं तथा अगर गहलोत पार्टी में भारी पद पर आ जाते है तो, वेणुगोपाल का पार्टी अध्यक्ष व पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण बरकरार रहता है।
- गहलोत की इन सारी कोशिशों के बावजूद यह माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अंततोगत्वा गहलोत पर विश्वास करने को शायद ही तैयार हों, क्योंकि गहलोत पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ खुलकर बगावत की थी, दो साल पहले।
- क्या, सोनिया गांधी, पार्टी का सुप्रीम लीडर का रुतबा खतरे में डालेंगी, बगावत करने वाले ''सिपाही'' का पुनर्वास करवा कर?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जनवरी। अशोक गहलोत ने ए.आई.सी.सी. में भारी पद पाने के लिये सारे घोड़े खोल दिये हैं।

उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि सर्वशक्तिमान के.सी. वेणुगोपाल इस आधार पर उनका समर्थन कर रहे हैं कि गहलोत कांग्रेस पार्टी के एक बड़े फायनैंसर हैं।

चूँकि वेणुगोपाल को महासचिव (संगठन) पद पर पूरे पाँच साल हो गये हैं, इसलिये ऐसी प्रबल अटकलें हैं कि उन्हें इस पद से हटाकर कोई अन्य पद दिया जा सकता है। लेकिन आज भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे राहुल गांधी के दाहिने हाथ तथा उनके सर्वाधिक विश्वसनीय व्यक्ति हैं तथा आज भी उन्हीं की चल रही है। ऐसी चर्चाएं हैं कि वे कांग्रेस अध्यक्ष के राजनैतिक सलाहकार बनना चाहते हैं, जिससे वे अध्यक्ष कार्यालय पर नियंत्रण कर सकें, तथा इसके साथ ही, अशोक गहलोत जैसे, अपने करीबी के महासचिव (संगठन) बनने की स्थिति में, पार्टी पर भी नियंत्रण रख सकें।

जहाँ तक गहलोत का प्रश्न है, वे दिल्ली में अपने पैर रखने की जगह तलाशने के लिए जबरदस्त लामबंदी कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि उन्होंने दो वर्ष पूर्व सोनिया गांधी के खिलाफ विद्रोह किया था।

गहलोत ऐसे एकमात्र नेता हैं, जो सोनिया गांधी को आँखें दिखा चुके हैं, उन्हें खुली चुनौती दे चुके हैं तथा उनके खिलाफ बगावत कर चुके हैं।

ऐसे परिदृश्य में, क्या गांधी परिवार सब कुछ भुलाकर उन्हें माफ कर सकता है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या गांधी परिवार उन पर फिर से भरोसा कर सकता है?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कट ऑफ से अधिक अंक वालों के लिये पद रिक्त रखें

जयपुर, 8 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में कट ऑफ से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए, उनके लिए पद रिक्त रखने को कहा है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश विष्णु कुमार व सैयद अहमद सहित अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

इस मामले से जुड़े अधिवक्ता अधिवक्ता आरपी सैनी व लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर के

- हाई कोर्ट में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 के मामले ने निर्देश दिये।

6961 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें प्रार्थी ने ओबीसी श्रेणी से आवेदन किया था। उसके ओबीसी श्रेणी में कट ऑफ से ज्यादा अंक हैं। इसके अलावा, उसके पास सीएमएचओ की ओर से जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र भी है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान, प्रार्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल किया था, लेकिन अंतिम चयन सूची में उसका नाम नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता के अनुभव और जीएनएम के अंक जोड़ने पर कुल अंक कट ऑफ से ज्यादा होते हैं। ऐसे में उसे चयन से वंचित रखना गलत है। इसलिए उसे चयनित कर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दी जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलुगू भाषी लोगों की प्रतिष्ठा व साख धूल चाट रही है अमेरिका में?

इतने टैक्निकल आई.टी. प्रोफेशनल अमेरिका जाते थे कि संयुक्त आंध्र एक ज़माने में अमेरिका का इक्यानवां राज्य कहलाने लगा था

- हैदराबाद में एक विशेष मंदिर, चिलुकुरु बालाजी, को वीसा मंदिर माना जाने लगा था, क्योंकि मान्यता बन गई थी कि अगर इस मंदिर में अमेरिका में वीसा मिलने की प्रार्थना करो तो शर्तिया वीसा मिलता है, जो हर तेलुगू भाषी युवा की पहली महत्वाकांक्षा थी।
- पर, अमेरिका ने 18,000 भारतीयों के वीसा रद्द करके, वापस भारत भेजने की कवायद शुरु की है। इन 18,000 लोगों में अधिकतर तेलुगू भाषी हैं।
- इन लोगों की प्रतिष्ठा धूल में मिलने का कारण है, इन तेलूगु भाषी आई.टी. विशेषज्ञों ने एक साजिश रचकर एपल कंपनी में भारी घोटाला, कई सालों से चला रखा था। बहुप्रतिष्ठित एपल कंपनी के तेलूगु भाषी कर्मचारी, तमिल एसोशिएशनों के सहयोग से करोड़ों डॉलर इकट्ठा कर इन एन.जी.ओ. को दान देते थे तथा एपल कंपनी दान को ''मैच'' करते हुए अपने सी.एस.आर. फंड से पैसा देती थी, पर एपल से पैसा मिलते ही कर्मचारियों का पैसा उन्हें वापस लौटा दिया जाता था। यह क्रम कई सालों से साल भर चलता था।

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जनवरी। तेलुगू भाषी लोग अमेरिका की सर्वाधिक प्रतिष्ठित फोन और लैपटॉप कंपनी, एपल के चहेते नहीं हैं। एपल ने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कई लोगों को, कंपनी की कॉरपोरेट सोशल रैस्पॉंसबिलिटी (सी.एस.आर.) स्कीम में कथित अनियमितताओं के लिए नौकरी से निकाल दिया।

यहाँ पहुँची खबरों के अनुसार, एपल ने कंपनी की सी.एस.आर. गतिविधियों की फर्जी अनुदान योजना में कथित रूप से लिप्त होने के आरोप में लगभग 185 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जिनमें से अधिकांश तेलुगूभाषी हैं।

रिपोर्टों में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें एपल के कर्मचारियों ने अमेरिका की कुछ तेलुगू संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके एपल की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

50 साल बाद नए भवन में शिफ्ट होगा कांग्रेस का मुख्यालय

कांग्रेस मुख्यालय का नया पता, 24, अकबर रोड से बदल कर इंदिरा गांधी भवन 9, ए कोटला रोड होगा

- कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी 15 जनवरी को सुबह दस बजे नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद होंगे।
- दिसम्बर 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. मनमोहन सिंह और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। निर्माण में पूरे 15 साल लगे हैं।
- सन् 1978 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो चुकी थीं और कांग्रेस भी टूट चुकी थी तब इंदिरा गुट के पास कार्यालय नहीं था। उस समय आंध्र प्रदेश के सांसद जी. वेंकट स्वामी ने अपना सरकारी आवास, 24, अकबर रोड कार्यालय के लिए दिया था।
- कांग्रेस पार्टी का आज़ादी के समय मुख्यालय 7, जंतर-मंतर रोड था, बाद में 5, राजेन्द्र प्रसाद रोड में मुख्यालय बना और फिर 1978 में 24, अकबर रोड मुख्यालय बनाया था।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जनवरी। लगभग 50 साल बाद, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय का पता बदलने जा रहा है। पच्चीस जनवरी को पार्टी मुख्यालय 24, अकबर रोड से इंदिरा गांधी भवन, 9-ए, कोटला रोड पर शिफ्ट हो जायेगा।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी 15 जनवरी को प्रात:10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फैसिलिटी का विधिवत् उद्घाटन करेंगी। लगभग 139 वर्ष की विस्तृत अवधि के इतिहास वाली कांग्रेस की समृद्ध विरासत के लिये यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। पार्टी 4, अकबर रोड को छोड़ रही है, जो सोनिया के आवास, 9, जनपथ के ठीक पीछे स्थित था। अब तक वे अपने आवास के पीछे के दरवाजे से पैदल ही पार्टी मुख्यालय पहुँच सकती थीं तथा पार्टी के नेतागण उसी दरवाजे से उनसे मिलने आ जाते थे। इस अवसर पर देश भर के प्रमुख पार्टी नेता एकत्रित होंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तिरुपति में भगदड़ में 6 की मौत

नई दिल्ली आंध्र प्रदेश , 08 जनवरी। तिरुपति में टोकन बंटने के दौरान मची भगदड़ में करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, वैकुंठद्वार सर्वदर्शनम टोकन वितरण के दौरान, तिरुपति के विष्णु निवासम में अफरा-तफरी मच गई, परिणामस्वरुप मची भगदड़ में इतना बड़ा हादसा हो गया।

जानकारी के अनुसार, टोकन प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण 6 लोगों की दुखद मौत हो गई, जिसमें तमिलनाडु के सलेम का एक श्रद्धालु भी शामिल है। घटना के दौरान चार

- दर्शन के लिये टोकन के वितरण के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भगदड़ मच गई।

अन्य लोग बीमार पड़ गए, उन्हें तुरंत इलाज के लिए रुइया अस्पताल ले जाया गया।

इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट में है। घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। भगदड़ को लेकर पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐन वक्त पर ऐंबुलेंस ड्राइवर गायब था, जिसके कारण घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई।

क्या हमें 6.65 प्रतिशत ग्रोथ रेट से संतुष्ट रहना चाहिये?

या, रियायतों के इंजैक्शन पर इंजैक्शन लगाकर कृत्रिम रूप से ग्रोथ रेट को 2021-22 की कोविड काल के बाद की ग्रोथ रेट तक खींचकर ले जाना चाहिये?

- यह बहस, पहली बार नहीं हो रही, भारत के इकॉनमिस्टों में, यह बहस छिड़ी है राजीव गांधी के समय, भारत के जाने-माने इकॉनमिस्ट डॉ. राजा चलैया एक तरफ थे तथा दूसरी तरफ थे, आबिद अली, पूर्व कॉमर्स सचिव।
- डॉ. चेलैया का सोच था, इकोनॉमी/जी.डी.पी. को अपनी स्वाभाविक स्वजनित रेट पर बढ़ने देना चाहिये। आबिद अली का तर्क था, सभी खिड़कियां खोल देनी चाहिये, नई शुद्ध हवा आने के लिए, अगर हवा के साथ कुछ मक्खियां भी आ जाती हैं तो उनसे हम बाद में निपट लेंगे।
- पर, यह सच है कि कृत्रिम तरीकों से रियायतों के इंजैक्शन लगाकर अगर ग्रोथ रेट बढ़ाई जाती है तो कई विकृतियां आ जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है तथा ग्रोथ दीर्घकालीन नहीं होती। अंततोगत्वा गिरती है, जिससे हौंसला टूटता है, निराशा बढ़ती है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जनवरी। जी.डी.पी. के नवीनतम अग्रिम अनुमानों की घोषणा होने के साथ ही कुछ लोग मान रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है और आने वाले कुछ वर्षों में 8 प्रतिशत या उससे अधिक विकास दर तक नहीं पहुंच पाएगी। उनका मत है कि निकट भविष्य में भारत की ग्रोथ रेट 6 से साढ़े 6 प्रतिशत तक रह सकती है।

तथ्यों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। वर्ष 2023-24 में भारत ने 8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट देखी है। नवीनतम आंकड़े 2024-25 के लिए 6.4 प्रतिशत की ग्रोथ रेट दर्शा रहे है। कोविड-19 के हासिल ऊंचाइयों के बाद यह बड़ी गिरावट है जब 2021-22 में ग्रोथ रेट 9.7 प्रतिशत थी। गत 13 सालों में 2012-13 से चार वर्षों में ग्रोथ रेट 8 प्रतिशत से अधिक रही है।

मौजूदा रुझानों के अनुसार भारत की जी.डी.पी. ग्रोथ रेट अधिकांश वर्षों में औसतन 7 प्रतिशत रही है और अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है बशर्ते असाधारण घटनाएं इसमें अड़चन ना डालें, जैसे वैश्विक महामारी या नोट बंदी आदि।

एक बड़ी अर्थव्यवस्था का बिना किसी कृत्रिम प्रोत्साहन के 7 प्रतिशत की दर से बढ़ना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ग्रोथ के उन्माद में ऐसी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए कि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन पैदा होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसकी बजाय इसे अपनी स्वाभाविक रफ्तार से बढ़ने देना चाहिए।

ग्रोथ का उन्माद समय-समय पर और महत्वपूर्ण मौकों पर नीति निर्माताओं और सामान्य पर्यवेक्षकों को प्रभावित करता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब पंचवर्षीय योजना निर्माण के दौरान भारी बहस छिड़ी थी। योजना आयोग दो गुटों में बंट गया था।

डॉ. राजा चेल्लैया जो उस समय के जाने माने अर्थशास्त्री थे और योजना आयोग के सदस्य थे, ने सतर्क सोच का समर्थन किया और सलाह दी थी कि ग्रोथ टारगैट ऐसा हो जो प्राप्त किया जा सके। वहीं दूसरे गुट के सदस्य आबिद हुसैन ने महत्वाकांक्षी योजना बनाने की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वी. नारायणन इसरो के नये प्रमुख बने

नयी दिल्ली, 08 जनवरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष वी. नारायणन होंगे। इसकी जानकारी मंगलवार को भारत सरकार ने दी। वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉ. एस. सोमनाथ की जगह लेंगे। वी नारायणन अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसार,

- नारायणन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। वे 14 जनवरी को कार्यभार सभालेंगे।

वी नारायणन 14 जनवरी को वर्तमान इसरो प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। वह अगले दो वर्षों तक या अगली सूचना तक इस पद पर रहेंगे। वी नारायणन एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, जिनके पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में लगभग चार दशकों का अनुभव है। वह एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारतीय मूल की अनिता आनंद कैनडा के प्रधानमंत्री पद की प्रमुख दावेदार के रुप में उभरीं

पर, सवाल यह है कि क्या इससे ही भारत और कैनडा के रिश्तों में सुधार हो जाएगा

- इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि, इसमें नए प्रधानमंत्री की नीतियां और कूटनीतिक नज़रिया महत्वपूर्ण होगा।
- सबसे प्रमुख मुद्दा है, खालिस्तानी आतंकवादियों का। कैनडा में बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थक रहते हैं। जस्टिन ट्रूडो द्वारा अब तक उन्हें संरक्षण दिया जाता रहा। भारत को उम्मीद है कि अगर अनिता आनंद प्रधानमंत्री बनीं तो वे इस मसले पर भारत की चिंताओं का समाधान करेंगी।
- अनिता आनंद कैनडा में कई विभागों की मंत्री रही हैं तथा कोविड-19 के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता का परिचय मिला, कोविड की वैक्सीन खरीदने में मिली सफलता से।
- विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-अमेरिका के संबंध और कैनडा-अमेरिका के संबंध भी भारत और कैनडा के आपसी रिश्तों को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जनवरी। जस्टिन ट्रूडो ने कैनडा के प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत -कैनडा के रिश्तों में सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका जवाब साधारण ''हां या ना'' नहीं है। इसका जवाब कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें उनके उत्तराधिकारी की नीतियां और कूटनीतिक लहजे के साथ दोनों देशों के भूराजनैतिक और आर्थिक हित शामिल होंगे।

ट्रूडो के बाद के संभावित परिदृश्य में जो नया नेता आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देगा और विवादास्पद मुद्दों का गैरराजनीतिकरण करेगा, वही दोनों देशों के रिश्तो में स्थिरता और शांति ला सकता है। दोनों देशों के कई क्षेत्रों में आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। जैसे टैक्नॉलजी, क्लीन एनर्जी व कृषि। दोनों देशों के परस्पर सहयोग से लाभ हो सकता है कैनडा में आतंकी तत्वों के रहने से जुड़ी भारत की चिंता के समाधान से तनाव दूर करने में मदद मिल सकती है।

कुछ मुद्दों, जैसे खालिस्तान आदि, का अगर समाधान नहीं किया गया तो ये हमेशा बने रह सकते हैं, भले ही किसी का भी नेतृत्व हो। कैनडा की घरेलू राजनैतिक गतिशीलता और प्रवासी राजनीति विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करना जारी रख सकती है।

उल्लेखनीय है कि अनिता आनंद, जो कैनडा की परिवहन और आन्तरिक व्यापार मंत्री हैं, का नाम ट्रूडो के उत्तराधिकारी के रुप में चल रहा है।

अनिता भारतीय मूल की हैं और 2019 से ओकविले, ओन्टारियो का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वे कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुकी हैं। रक्षा मंत्री के रुप में उन्होंने कैनडा की सेना में यौन उत्पीड़न संबंधी सुधार शुरु किए, सांस्कृतिक बदलाव को प्रोत्साहन दिया। कोविड -19 के दौरान, उनके नेतृत्व को पहचान मिली, क्योंकि उन्होंने कैनडा के लिए वैक्सीन हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संयुक्त राष्ट्र ने एच.एम.पी.वी. को सामान्य सर्दी जुकाम बताया

नयी दिल्ली, 08 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मानव मेटान्यूमो-वायरस (एचएमपीवी) सामान्य सर्दी ज़ुकाम है जो शिशिर और बसंत ऋतु में होता है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एचएमपीवी नया वायरस नहीं है। इसे सर्वप्रथम वर्ष 2001 में पहचाना गया और यह लंबे समय से मानव समाज में

- संयुक्त राष्ट्र की सोशल पोस्ट में कहा गया है कि इस वायरस को 2001 में पहचाना गया था।

मौजूद है।

पोस्ट में कहा गया कि, यह सामान्य वायरस है जो सामान्य सर्दी ज़ुकाम की तरह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।

पोस्ट के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्ल्यूएमओ की वरिष्ठ अधिकारी मार्ग्रेट हैरिस का एक बयान भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)